क्रमांक 15011/36/2022-जेयूएस(एयू)/ई6889
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषयः न्याय विभाग के संबंध में जून, 2024 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग से संबंधित जून, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. <u>ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना</u>:

क. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)**: मई 2024 माह के दौरान, कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 18 लाख से अधिक मामलों और 25 लाख से अधिक आदेशों/निर्णयों की जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल (एनजेडीजी) में जोड़ी गई थी।

ख. **वर्चुअल कोर्ट**: मई 2024 के दौरान, 25 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 15,12,177 मामलों की सुनवाई की गई है, और 1,37,998 मामलों में 13.34 करोड़ रुपये की ऑनलाइन जुर्माना राशि वसूल की गई है।

ग. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**: फरवरी 2024 से मई 2024 तक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वीसी मोड का उपयोग करके 1,01,909 मामलों की सुनवाई की।

घ. **जजों के लिए JustIS ऐप डाउनलोड**: **JustIS** मोबाइल ऐप को मई, 2024 माह में 26 और व्यक्तियों ने डाउनलोड किया है।

2. <u>न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना</u>:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें ग्राम न्यायालय की योजना के लिए आवंटित 2.00 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इसमें से इस योजना के तहत 24.570 करोड़ रुपये की राशि जून, 2024 माह में जारी की जा चुकी है।

3. <u>टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंचना</u>:

क. इस माह के दौरान 3,45,168 लाभार्थियों को और जून, 2024 तक कुल 89,57,712 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई।

ख. ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) न्याय सहायकों, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 88 जिलों में आयोजित 93 जागरूकता सत्रों/शिविरों में 1988 व्यक्तियों ने भाग लिया।।

ग. 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 134 जिलों में आयोजित 110 प्रशिक्षण सत्रों में 4,611 व्यक्तियों ने भाग लिया।

4. <u>न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम</u>:

न्याय बंधु एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 63 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत किया गया। अब तक, 11,146 (पुरुष-9336, महिला-1808, ट्रांसजेंडर-02 प्रो बोनो वकीलों को न्याय बंधु पोर्टल के तहत शामिल हो चुकें हैं।

5. <u>लॉ स्कूलों के प्रो बोनो क्लबों द्वारा संचालित गतिविधियां/कार्यक्रम</u>

क. विवेकानन्द स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (वीएसएलएलएस), विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (वीआईपीएस) यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के प्रो बोनो क्लब ने नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।

ख. पी.जी. विधि विभाग, बेरहामपुर विश्वविद्यालय के प्रो बोनो क्लब ने नव अधिनियमित आपराधिक कानूनों पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की।

6. <u>कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):</u>

क. शैडो एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड भुवनेश्वर, ओडिशा ने मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अपना डिजिटल कानूनी साक्षरता अभियान जारी रखा और घरेलू श्रमिकों और पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों से संबंधित कानूनों को शामिल करके 9,378 दर्शकों तक पहुंच बनाई। इसके तहत एक मीडिया वैन अभियान 19 जून, 2024 को शिक्षा के अधिकार पर शुरू किया गया था और यह सीधे ओडिशा के खोर्धा, कटक, नयागढ़ और गंजम जिलों के 3,360 ग्रामीणों तक पहुंचा।

ख. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु ने 1 जून, 2024 को क्रिस्टु जयंती कॉलेज ऑफ लॉ, बेंगलुरु में 300 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 'कानूनी सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम' शुरू किया। एनएलएसआईयू ने 28.06.2024 को 93 प्रतिभागियों के साथ 'किशोर न्याय की रूपरेखा' पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।

ग. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुणे ने 6-7 जून, 2024 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस परिसर तुलजापुर, धाराशिव, महाराष्ट्र में 100 विधि दूतों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 726 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज पदाधिकारियों ने 3 नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

घ. मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए),ने शिक्षा विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विलियमनगर और राज्य सरकार के अन्य विभागों के सहयोग से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की योजनाओं और सरकारी कल्याण योजनाओं पर एक मेगा शिविर-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और "बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलना/स्कूल वापसी अभियान" शीर्षक से एक अभियान भी 22 जून, 2024 को रोंगरेन्गिरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड, विलियमनगर, ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मेघालय में शुरू किया। इस कार्यक्रम में करीब 1500 लोगों ने हिस्सा लिया।

ङ. डॉ. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (एजीएलसी), पुडुचेरी ने पुडुचेरी के 4 स्कूलों में 4 न्याय ओली क्लबों का उद्घाटन किया। एजीएलसी ने चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और 670 प्रतिभागियों तक पहुंच बनाई।

च. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 28 जून, 2024 को अपने ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर एक इंटरैक्टिव सत्र देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे और कानून के साथ संघर्ष में बच्चे' का आयोजन किया और 81 दर्शकों तक पहुंच बनाई।

7. <u>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए):</u>

नालसा के तत्वावधान में, 8 जून, 15 जून, 22 जून और 29 जून 2024 को 09 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों के स्तर पर आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 9.38 लाख से अधिक प्रि-लिटिगेशन मामले और 11.26 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

*****